

This being the 2000th branch of the bank and that too in an unbanked area, the State Bank of India utilised this occasion to publicise its achievements and objectives by issuing advertisements in about 90 newspapers etc., both English and Indian languages, all over the country by incurring an expenditure of R.S. 1,09,000 from its general funds for publicity and another sum of Rs. 36,487.50 towards film shows, posters and souvenirs,

#### गुजरात में नये कालेज

578. श्री ना० कृ० शेजवलकर :

श्री मानसिंह वर्मा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की हाल में हुई बैठक में यह ग्राम राय प्रकट की गई थी कि भविष्य में केवल उन्हीं कालेजों को मान्यता दी जाये जो पिछड़े क्षेत्रों में खोले जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

#### NEW COLLEGES IN GUJARAT

478. SHRI N. K. SHEJVVALKAR :  
SHRI MAN SINGH VARMA :

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE/वि० श० अ० शेजवलकर/वि० म० व० वरमा be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it was a general opinion in a recent meeting of the Vice-Chancellors of the Universities situated in Gujarat that in future only those colleges should be granted recognition which are opened in backward areas; and

(b) if so, what is the Central Government's reaction in regard thereto? ]

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) गुजरात सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार, बैठक में कुलपतियों की ग्राम राय यह थी कि भविष्य में केवल उन्हीं कला, वाणिज्य तथा विधि कालेजों को सम्बद्ध किया जाना चाहिए। जो सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाते हैं।

(ख) नये कालेजों के खोलने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। गुजरात सरकार पहले ही यह निर्णय कर चुकी है कि जून, 1969 से प्रारम्भ किये गये नये कला तथा वाणिज्य कालेजों को अनुदान न दिया जायगा और इसके पश्चात् केवल उन कालेजों को, जो सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े तालुकों में स्थित हैं !

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE/श्री डी० पी० यादव] : (a) According to the information furnished by the Gujarat Government, the general opinion of the Vice-Chancellors in the meeting was that in future only those Arts, Commerce and Law Colleges should be granted affiliation which are opened in the backward areas notified by the Government.

(b) Opening of new colleges is the responsibility of the State Governments. The Gujarat Government has already decided not to pay grant to new Arts and Commerce Colleges started from June 1969 and thereafter except to those situated in the backward Talukas notified by the government.]

#### उत्तर प्रदेश में उद्योगों को ऋण

479. श्री नगेश्वर प्रसाद शाही :

श्री सीता राम सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और झाजमगढ़ जिले के कितने लघु औद्योगिक एककों को 1-1-1970 से 31-3-1971 तक के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये गये; और

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उपरोक्त जिलों में लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता की जरूरत है ?

#### LOANS TO INDUSTRIES IN U.P.

479. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI : SHRI SITARAM SINGH : Will the Minister of FINANCE/श्री सी० रा० सिंह be pleased to state :

[ ] English translation.

(a) the number of small-scale industrial units in the Districts of Gorakhpur, Basti, Devria and Azamgarh of Uttar Pradesh which were granted loans by the nationalised banks during the period from 1st January, 1970 to 31st March, 1971; and

(b) the amount of financial assistance given by the nationalised banks to the small-scale industries in the above-mentioned Districts since the nationalisation of banks and the amount of financial assistance required to meet their demands in toto?]

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जिन लघु औद्योगिक एककों को ऋण मंजूर किये जाते हैं, उनकी संख्या या उन्हें दी गयी वित्तीय सहायता की राशि के सम्बन्ध में आंकड़े बैंकों द्वारा राज्यवार गये जाते हैं, जिलावार नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में ये विवरण नीचे दिये गये हैं :—

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गए ऋण**

(लाख रुपयों में)

	एककों की संख्या	वर्तमान सीमा	बकाया शेष
जून, '69 के अन्त तक	4,612	4,024.61	1,807.33
दिसम्बर, '70 के अन्त तक	8,188	5,398.35	2,814.90

इन जिलों के लघु औद्योगिक एककों की वित्तीय सहायताओं के सम्बन्ध में अनुमान लगाना संभव नहीं है।

[THE MINISTER OF FINANCE/faTT\*PiJt (SHRI Y.B. CHAVAN) : (a) and (b) : Data about the number of smallscale units granted loans by the nationalised or public sector banks or the amount of financial assistance given to them is maintained by the banks only Statewise and not Districtwise.

Particulars in their regard for the State of Uttar Pradesh are as given below:

[ ] English translation.

**Advances made by Public Sector Banks**

(Amount in Rs. lakhs)

	No. of Units in force	Limit Outstanding
End of June 69.	4,612	4,024.61
End of Dec. 70.	8,138	5,398.35
		2,814.90

It is not possible to estimate the financial requirements of small-scale units in these districts.]

**नीवहन के लिये माल भाड़े की दरें**

480. श्री बी० एन० मण्डल : क्या संसदीय कार्य तथा नीवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन डब्ल्यू शिपिंग काउन्सिल के चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन में उसके अध्यक्ष श्री एल०एन० बिड़ला ने कहा है कि विदेश व्यापार के मिलमिल में जिस माल का निर्यात होता है, उसका किराया बहुत ज्यादा और मनमाना है ;

(ख) क्या श्री बिड़ला या किसी अन्य व्यक्ति ने इस दोष को दूर करने के लिए कोई सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग 'ख' का उत्तर 'हां' हो, तो वे सुझाव क्या हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†FREIGHT RATES FOR SHIPPING GOODS

480 SHRI B. N. MANDAL : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT/

be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Fourth Annual Conference of the All India Shipping Council, its Chairman, Shri L.N. Birla said that the freight rates for shipping goods that are exported in the course of foreign trade are exorbitantly high and arbitrary.

(b) whether Shri Birla or any other agency has made some suggestions in order to do away with this anomaly, and

(c) if the answer to part (b) above to in the affirmative, what are those suggestions